

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

‘हर काम देश के नाम’

नई दिल्ली: आश्विन05, 1944

मंगलवार: 27सितंबर 2022

रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा उद्योग से 'नए भारत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए अत्याधुनिक व लागत प्रभावी उत्पादों की पहचान करने और उनका निर्माण करने का आह्वान किया

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया

राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं: श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एसआईडीएम के पांचवें वार्षिक सत्र में कहा

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा उद्योग से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'नए भारत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए अत्याधुनिक व लागत प्रभावी उत्पादों/प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और उनका निर्माण करने का आह्वान किया है, जो न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। उन्होंने 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (एसआईडीएम) के 5वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया।

श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रणाली के महत्व को पूरी तरह से समझती है और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी आयामों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केवल एक सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र ही प्रगति की सर्वोच्च ऊंचाइयां छूने में सक्षम हो सकता है। कोई राष्ट्र कितना ही धनवान या ज्ञानवान क्यों न हो, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है तो उसकी समृद्धि खतरे में रहती है। हम भारत को दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी मानते थे और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार बड़े उत्साह के साथ उस परिकल्पना को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारों की संख्या ने रक्षा कंपनियों के लिए देश के समग्र विकास के साथ-साथ अपने स्वयं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है।

श्री राजनाथ सिंह ने 2022-23में घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68प्रतिशत निर्धारित करने सहित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया, जिसमें से 25प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25प्रतिशत निजी उद्योग और स्टार्ट-अप के लिए निर्धारित किया गया है जो भारत में नई रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा। अन्य उपायों में सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी करना; रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020का अनावरण; रणनीतिक साझेदारी मॉडल और रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडेक्स) पहल के माध्यम से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक और पनडुब्बियों सहित मेगा रक्षा कार्यक्रम के निर्माण के अवसरों को खोलना, जिसने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के लिए पारिस्थितिकी प्रणाली बनायी है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि लगातार विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य के कारण दुनिया भर में सैन्य उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे देश अपनी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने उद्योग जगत से भारतीय रक्षा क्षेत्र के इस स्वर्णिम काल का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए उन्हें 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित दो रक्षा गलियारों में निवेश बढ़ाकर अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा, "स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2021में, विश्व सैन्य खर्च पहली बार दोट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। इसमें 2020की तुलना में 0.7प्रतिशत और 2012की तुलना में 12प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हमारे सशस्त्र बल आने वाले वर्षों में पूंजीगत खरीद में भी अच्छी खासीधनराशि खर्च करेंगे। इससे

पता चलता है कि दुनिया की सुरक्षा जरूरतें बढ़ना तय है। भारत उन जरूरतों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती तरीकों से पूरा करने में सक्षम है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और अनुसंधान एवं विकास संगठनों को एसआईडीएम के साथ मिलकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए।”

रक्षा मंत्री ने इस तथ्य की सराहना की कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं, जैसा कि घरेलू उद्योग को दिए गए अनुबंधों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 10,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) रक्षा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जिसमें अनुसंधान और विकास, स्टार्ट-अप, नवाचार और रोजगार में वृद्धि देखी जा रही है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “सात-आठ साल पहले हमारा रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ रुपये भी नहीं था। वह अब 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हमने 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।”

रक्षा श्रेयों में हाल के उछाल पर, रक्षा मंत्री ने कहा कि कंपनियों का बढ़ता बाजार मूल्यांकन बड़े निवेशकों, सेवाओं और राष्ट्र के उन संस्थाओं में विश्वास को दर्शाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं।

एसआईडीएम को सरकार और उद्योग के बीच एक सेतु बताते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कंपनियों से आग्रह किया कि वे एसोसिएशन से उनकी किसी भी शंका और शिकायत के बारे में बात करें और रक्षा मंत्रालय के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दें। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उद्योग का बैलेंस शीट के साथ-साथ राष्ट्र के प्रति भी उत्तरदायित्व है। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और विक्रेताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला में समय पर भुगतान करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट सामाजिक

उत्तरदायित्व का निर्वहन करने सहित सभी हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखने का आह्वान किया।

रक्षा मंत्री ने एसआईडीएम के विकास की सराहना करते हुए कहा कि इसकी स्थापना के केवल पांच वर्षों में, लगभग 500 सदस्य एसोसिएशन में शामिल हो गए हैं, जो भारतीय रक्षा उद्योग की प्रगति का संकेतक है। उन्होंने दिल्ली से बाहर एसआईडीएम के विस्तार को उद्योग के विश्वास के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के मुख्य उद्देश्य के साथ स्थानीय कंपनियों के हितों की रक्षा करने के एसोसिएशन के संकल्प को प्रदर्शित करने के रूप में वर्णित किया।

एसआईडीएम का 5वां वार्षिक सत्र 'इंडिया@75: शेपिंग फॉर इंडिया@100' विषयवस्तु पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा विनिर्माण में शीर्ष देशों में से एक के रूप में स्थापित करना था। इस सत्र में रक्षा मंत्रालय के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय सशस्त्र सेनाओं, उद्योग जगत और भारत स्थित विदेशी रक्षा अताशे ने भाग लिया। इस अवसर पर वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, सह नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल एस एन घोरमडे, सह थलसेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू, एसआईडीएम के अध्यक्ष श्री एसपी शुक्ला भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने एसआईडीएम चैंपियंस अवार्ड के दूसरे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड उन विजेताओं में शामिल थे, जिन्हें क्षमता अंतराल को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार, आयात प्रतिस्थापन और डिजाइन/विकास और परीक्षण के लिए बुनियादी संरचना जैसी विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

एबीबी/डीएस